

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग
संख्या: 608 /VII-1/2013/146-ख/2010
देहरादून : दिनांक: 22 मार्च, 2013

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या 2911/VII-II/146-ख/10/2011, दिनांक 18 नवम्बर, 2011 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011 में निम्नवत् संशोधन एवं अतिरिक्त प्राविधान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011 के प्रस्तर-1 व 3 के स्थान पर प्राविधान प्रतिस्थापित एवं बिन्दु संख्या-4 (सरकारी कार्यदायी संस्थाओं के सम्बन्ध) में 4 (1) अतिरिक्त प्राविधान रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

वर्तमान प्राविधान

2. उपखनिज

राज्य के राजस्व नदी उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज के चुगान के खनन पट्टे गढ़वाल मण्डल में गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा कुमाऊँ मण्डल क्षेत्र में कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को तथा वन क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले नदी तल के उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज के चुगान के खनन पट्टे उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र एम0एम0-1 में आवेदन करने के उपरान्त पांच वर्ष हेतु स्वीकृत किये जायेंगे। निगमों के द्वारा उपखनिज के चुगान/खनन कार्य स्वयं किया जायेगा तथा किसी को सबलेट नहीं किया जायेगा। निगम खनिजों की रायल्टी पर 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान

2. उपखनिज

राज्य के राजस्व नदी उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज के चुगान के खनन पट्टे गढ़वाल मण्डल में गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा कुमाऊँ मण्डल क्षेत्र में कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को तथा वन क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले नदी तल के उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज के चुगान के खनन पट्टे उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र एम0एम0-1 में आवेदन करने के उपरान्त पांच वर्ष हेतु स्वीकृत किये जायेंगे और ऐसे उपखनिज क्षेत्रों के लिए उपलब्ध उपखनिज की मात्रा पर आंकलित धनराशि के सापेक्ष आंगणित होने वाली रायल्टी की धनराशि/पट्टा धनराशि पर वार्षिक 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ निगमों द्वारा अग्रिम रूप से जमा करायी जायेगी। निगम खनिजों की रायल्टी पर 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

निगमों द्वारा खनन कार्य Tender के माध्यम से चयनित व्यक्ति/संस्था के माध्यम से कराया जायेगा।

उक्त Tender में 5.00 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के लिए जिले स्तर पर जनपद के स्थायी निवासी/स्थायी निवासियों की समिति जो सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हो, तथा 5.00 हैक्टेयर से ऊपर के लिए राज्य के स्थायी निवासी/स्थायी निवासियों की समिति जो सोसाइटीज एक्ट अथवा कम्पनीज एक्ट अथवा पार्टनरशिप एक्ट एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत हो, तथा निजी व्यक्तियों को आवंटित किया जायेगा।

Open Tender में चयन हेतु उपलब्ध उपखनिज की मात्रा पर रायल्टी की आगणित धनराशि जिसका उल्लेख निविदा में किया जायेगा पर अधिकतम धनराशि की बोली लगाने वाले निविदाकर्ता को पात्र मानते हुए चयन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि० को 1000 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि० को 250 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक तथा उत्तराखण्ड वन विकास निगम को 7000 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक के खनन लाट एक वर्ष की अवधि के लिए आवंटित किये जायेंगे।

(3) ऐसे उपखनिज क्षेत्र जिसमें निगमों के द्वारा उपखनिज का चुगान कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है या ऐसे क्षेत्र जिनमें उपलब्ध खनिजों की पूर्ण क्षमता का दोहन करने में अक्षम पाये जाते हैं, या ऐसे क्षेत्र जो निगमों के द्वारा रिक्त छोड़ दिये जाते हैं, को नियमानुसार टेन्डर प्रक्रिया के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य विपणन संघ/भ्रम संविदा समितियों/कॉर्पोरेटिव सोसाइटियों/संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों को पांच वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टे स्वीकृत किये जायेंगे।

(3) निगमों द्वारा छोड़े गये लाटों की पर्यावरणीय स्वीकृति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा करवाते हुए निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा घोषित खनन लाटों को टेण्डर के माध्यम से 5.00 हैक्टेयर तक के खनन लाट जनपद स्तर पर जनपद के स्थायी निवासी/स्थायी निवासियों की समिति जो सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हो, तथा 5.00 हैक्टेयर से ऊपर तक खनन लाट राज्य के स्थायी निवासी/स्थायी निवासियों की समिति जो सोसाइटीज एक्ट अथवा कम्पनीज एक्ट अथवा पार्टनरशिप एक्ट एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत हो, तथा निजी व्यक्तियों को आवंटित किया जायेगा।

Open Tender में चयन हेतु उपलब्ध उपखनिज की मात्रा पर रायल्टी की आगणित धनराशि जिसका उल्लेख निविदा में किया

जायेगा पर अधिकतम धनराशि की बोली लगाने वाले निविदाकर्ता को पात्र मानते हुए चयन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011 के बिन्दु संख्या-4 (सरकारी कार्यदायी संस्थाओं के सम्बन्ध) में निम्नवत् 4(1) अतिरिक्त प्राविधान :-

- 4(1) जनपद के सरकारी निर्माण कार्य हेतु निर्माण एजेंसियों के द्वारा उसी जिले से एस्टीमेट के अनुसार निर्माण सामग्री क्रय कर उपयोग किये जाने की अनिवार्यता की जाये। यदि किसी कारणवश उक्त निर्माण सामग्री उक्त जनपद में उपलब्ध न हो तो सम्बन्धित जिलाधिकारी से खनिज अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही निर्माण एजेंसियों द्वारा निर्माण सामग्री अन्य जनपद से क्रय की जाने की व्यवस्था करनी होगी।

उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।


(शिक्षा शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 608 (1)/VII-1/2013/146-ख/2010, तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ उत्तराखण्ड।
5. निदेशक उद्योग/भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, भोपालपानी, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम/कुमाऊँ मण्डल विकास निगम/उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
8. गोपन अनुभाग।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की-हरिद्वार को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
11. गार्ड फाईल।


आज्ञा से,
(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।